

क्रमांक 160-3 एस-70, 9698

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

दिनांक चण्डीगढ़ : 23 अप्रैल, 1970 ।

विषय :- नेशनल इंटरग्रेशन कांसल द्वारा बनाई गई साम्प्रदायिकता के बारे में कमिटी की सिफारिशें ।  
महोदय,

मुझे श्री आर० डी० यापर, संयुक्त सचिव, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, के उपरोक्त विषय पर अ० स० पत्र क्रमांक 9/29/68 ए० आई० एस० (III) दिनांक 24 दिसम्बर, 1968 की प्रति आपको मार्ग दर्शन के लिये भेजने का आदेश हुआ है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि आई० ए० एस० व एच० सी० एस० अधिकारियों के काम पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय उनकी साम्प्रदायिक खिचाव व गड़बड़ को दूर करने की योग्यता को ध्यान में रखा जाये । इस पत्र को जिला के सभी आई० एस० एस० व एच० सी० एस० अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन के लिये ध्यान में भी लाया जाये ।

भवदीय,

आर० डी० माथूर,

अवर सचिव (प्रशासन)

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 160-3एस-70/9698, दिनांक चण्डीगढ़ 23 अप्रैल, 1970 ।

एक प्रति, अनुलग्नक की प्रति सहित, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी, को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

2. उनसे अनुरोध है कि वे उपायुक्तों आदि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय उनकी साम्प्रदायिक खिचाव व गड़बड़ को दूर करने की योग्यता को ध्यान में रखें ।

एक प्रति सचिव, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 5531/-3 एच-69 दिनांक 25 मई 1969 के हवाले में सूचनार्थ भेजी जाती है ।

एक प्रति गृह आयुक्त हरियाणा को उनके आशासकीय क्रमांक 12623-3एच-69, दिनांक 5 जनवरी 1970 के हवाले में सूचनार्थ भेजी जाती है ।

Copy of D.O. No. 9/29/68-A1S (III) dated 24-12-68 from Shri R. D. Thapar Joint Secretary to Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi to Shri Saroop Krishan, Chief Secretary to Government Haryana, Chandigarh.

Kindly refer to Shri T. C. K. Srinivasavaradan's D.O. letter No. 28/3/68-poll. I (A), dated July 20, 1968 regarding the recommendations of the National Integration Council.

2. The Committee on Communal Aspects appointed by the National Integration Council had recommended that the District Magistrate and Supdt. of Police should be made personally responsible for prompt action to prevent or stop communal disturbances. They had further recommended that failure to take prompt and effective action should be considered as dereliction of duty and the officer concerned should be dealt with accordingly. The Committee felt that, if necessary, service rules should be amended. A related recommendation was that a system of suitable recognition of services rendered in preventing or dealing with communal disturbances should be introduced.

3. I am desired to request that the attention of all members of the I.A.S. and I.P.S. may be specifically invited to the recommendations of the National Integration Council, and it may be impressed upon them that any failure to take effective action to deal with communal tensions and disturbances would be regarded by Government as a dereliction of duty entailing suitable disciplinary action.

4. Officer reporting on the work and conduct of executive District/Sub Divisional/City Magistrates etc. and Superintendents/Assistant Superintendents of Police may also be suitably advised to take into account will be evaluation of their performances the effectiveness of otherwise of the officers working under their supervision in dealing with situations of this nature.

5. I shall be grateful if copies of the instructions issued in this behalf are endorsed to this Ministry for reporting to the Standing Committee of the National Integration Council on the progress of action taken on the recommendations of the National Integration Council.